and publishers for producing books of an acceptable standard at reasonable prices for students and teachers of Indian Universities and technical institutes under its scheme for the subsidised publication of books. The books are published in English, Hindi or in any other language listed in the 8th schedule of the constitution.

The books subsidised under the scheme are those for which a definite need is felt and which relate to subject areas where books of an acceptable standard are either not available or are so highly priced to be beyond the means of the majority of students.

The author receives royalty equal to 20% of the published price of the subsidised edition of the book, directly from the Trust, on publication of the book. The publisher is paid 50% of the total cost of production of the book, as subsidy.

Over 800 titles have been subsidised under the scheme since its inception in 1970.

Need to Check Brahmaputra's Floods ta Jorhat Town

733. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the river Brahmaputra is now only fow kilometers away from the Jorhat town and the only protective measure to check the southward advance of its course is the only embankment at a distance of one Km. from the Nimati Ghat, which is also in danger; and

(b) if so, what action has been taken by Government tn this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) The Brahmaputra river is about twelve kilometers away from the Jorhat town. At present, the embankment on left bank from Hatisal to Neamatighat-Dainigaon and in downstream of Kokilamukh is providing protection to Jorhat twon from floods in Brahmaputra. The erosion of the left bank on river Brahmaputra at Neamatighat is tending to move southwards towards the embankment and the embankment is presently 1.00 to 1.50 kilometer away from river bank.

(b) To check the shift of Brahmaputra river course in southward direction due to erosion at the Hatisal-Neamatighat areas Government of Assam has submitted to the Union Government in July, 1995 an anti erosion scheme titled 'Protection of Dainigaon-Hatisal-Neamatighat area against the erosion of Brahmaputra river' at an estimated cost of about Rs. 32 crore. The scheme is under appraisal by the Central agencies.

अनिवासी भारतीयों द्वारा इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

734. **श्री बिमन भाई हरिभाई शुक्ल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश के विभिन्न भागों मे इस्पात संयंत्र व अन्य संबद्ध इकाइयां स्थापित करने हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उपर्युक्त प्रस्तावों में से उन प्रस्तावों की संख्या क्या है जिन्हें सरकार ने मंजूर कर दिया है; और

(ड) प्रत्येक प्रस्ताव में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और उन राज्यों के क्या नाम है जहां प्रस्तावित संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष महोन देव) : (क) से (ड) निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों और अन्य संबद्ध इकाइयों की स्थापना करने के लिए अप्रवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षो के दौरान निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र और अन्य संबद्ध इकाइयां स्थापित करने के लिए अप्रवासी भारतीयों और विदेशी कम्पनियों से प्राप्त का ब्यौरा

क्रम सं0	कम्पनी का नाम तथा स्थान	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम (निवेशक)	विनिर्माण की मद तथा क्षमता	विदेशी साम्या शेयर % तथा परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स निष्योन डेनरी इस्पात लिमिटेड, दोवली रायगढ़, महाराष्ट्र ।	मैसर्स इस्पात मेरिकाना मैक्सिको ।	एच0आर0 क्वायलें 10 लाख टन वार्षिक	25%(150 करोड़ रुपये) परियोजना लागत 2200 करोड़ रुपये (अनुमानित)	सरकार द्वारा मंजूर
2.	मैसर्स आरिन्ड स्टील्स लिमिटेड क्योझर उडीसा (दैतारी में चरण-1)	मैसर्स गोल्ड स्टार इन्वेस्टमेंट लिमिटेड), दुबई, यू एस एक्स इंजीनियर्स एण्ड कंसलटेन्टस इंक, यू एस ए	हाट एण्ड कोल्ड क्वाक्लें/शीत आदि क्षमता-7,00,00 टन वार्षिक (सी आर सी-चरण-1) 10,00,000 टन वाल र्षिक (एच आर सी/सी आर सी-चलरण-॥0	44.44 %(400 करोड़ रु0) परियोजना लागत 1650 करोड़ रुपये (646करोड़ रुपये चरण-। के लिए)	सरकार द्वारा मंजूर ।
3.	मैसर्स फिड-ईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लिमिटेड, कलिंगा नगर इण्डस्ट्रियल कम्पलैल वस, उडीसा ।	मैसर्स चीन मेटलार्जिकल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, चीन ।	कच्चा लोहा 0.40 लाख टन वर्षिक, इस्पात श्लाका तथा छ्ड़े और स्ट्रक्चरल 4.10 लाख टन वार्षिक (100%निर्यातोन्मुखी)	(क) 9% (25 करोड़ रुपये) (ख) अप्रबासी भारतीय 25 करोड़ रुपये परियोजना लागत (691.85 करोड़ रु0)	सरकार द्वारा मंजूर
4.	मैसर्स फिड-ईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लिमिटेड,कलिंगा नगर इण्डस्ट्रियल कम्पेलेल वस, उडीसा	मैसर्स चीन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन चीन ।	कच्चा लोहा 2.0 लाख टन वार्षिक, इस्पात श्लाका तथा स्ट्रक्चरल इस्पात 10 लाख टन वार्षिक (शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी)	(क) 20.4% (100 करोड़ रु0) (ख) अप्रवासी भारतीय 78 करोड़ रुपये परियोजना लागत 147 करोड़ रु0	सरकार के विचाराधीन
5.	मैसर्स मेस्वनेकलिंगा स्टील लिमिटेड, कलिंगा नमर इण्डस्ट्रियल कम्पलैक्स जिला जाजपुर, उडीसा	मैसर्स डेवइली एण्ड कम्पनी, इटली, यूनाइल टेड इंजीनियरिंग इंक, यू एस ए सानरांग कारपोरेलशन कोरिबामिल्सुई एण्ड कम्पनी जापान	एच आर क्यायल 13 लाख टन वार्षिक कच्चा लोहा 50 लाख टन वार्षिक (100% निर्याल तोन्मुखी)	12.5% (115 करोड़ रु0) एन आर आई साम्या (रिपेटरीकेबल) 20%) 183 करोड़ रु0) कुल परियोजना लागत 2746 करोड़	सरकार द्वारा मंजूर

1	2	3	4	5	6
6.	मैसर्स कीमुरा टील लिमिटेड, गांव-कुदियाणा तालुक-ओलपाडजिला-सूल रत राज्य-गुजरात	एन आर आई	इलेक्ट्रोड क्वालिटी वाल पर 75,000 टन रुपये) वार्षिक	24% (75.00 लाख रुपये)	सरकार द्वारा मंजूर
7.	मैसर्स नागार्जुन कैमिकल एण्ड कर्टीलाईज़र्स लि0 कनारा, मंगलौर कर्नाटक ।	एन आर आई	एच आर कॉयल्स-2.2 एम0टी0पी0ए0 (100%ई0ओ0यू)	10% (80 करोड़ रुपये	सरकार के विचाराधीन
8.	मैसर्स मिड-ईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील लि- कलिंगा, नागर इंडस्ट्रियल कांप्लैक्स उडीसा ।	मैसर्स चाइना मैटेलार्जिल कल इंपोर्ट एण्ड एक्सल पोर्ट कारपोरेशन, चाइना	पिग आयरन कैप 0.464 एम0टी0पी0 ए0	4.55% (538.3 लाख होल्डिंग 1846.36 लाख रुपये परियोजना लागत 220 करोड़ करोड़ रुपये।	सरकार द्वारा मंजूर
9.	मैसर्स लैको-फैरो लि0 ग्राम पंचगुनेरी, जिला-चित्तूल आंध्र0प्र0 ।	एशियन फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमैंट कारपोरेशन लिमिटेड सिंगापुर ।	पिग आयरन कैप 90,000 टी0पी0ए0	10.15%(2.32 करोड़ा रु0) +एन0आर0आई0 होल्डिंग 22.88%) 500 लाख रुपये)	सरकार द्वारा मंजूर
10.	मैसर्स तारा इंटरनेशनल जिला-रैजाद महाराष्ट्र ।	मैसर्स एफ0के0आर0एल ल0 जापान ।	प्रोसेस्ड स्क्रैप 12000 टी0पी0ए0	23.08% (6 लाख सरकार रुपये) परियोजना लागत 87 लाख रुपये	सरकार द्वारा मंजूर
11.	मैसर्स वोल्वो स्क्रैप इब्लिंग (आ0) लि0 महुरा, भावनगर गुजरात ।	एन0आर0आई0	प्रोसेड स्क्रैप 12000 टी0पी0ए0	25% (6.25 लाख) परियोजना लागत 66 लाख रुपये ।	सरकार द्वारा मंजूर
12.	मैसर्स फ्लोवर इंडिया लि0 पट तमिलनाडू ।	एन0आर0आई0	प्रोसेइड स्क्रैप 35000 टी0पी0ए0	3% (10 लाख रुपये)	सरकार द्वारा मंजूर
13.	मैसर्स निचौमैन कारपोरेशन सोसिया, गुजरात ।	प्रमुख भागीदारी सहित निजीमैन कारपोरेशन द्वारा प्रवर्तित विदेशी स्वामित्व का संयुक्त उद्यम ।	शिपकोकिंग ऑपरेशंस ऑफ वी0एल सी0 सी0एस0एण्ड ओ0 एल0 सी0सी0एस0 3-4 एल0डी0टी0	6.41 करोड़ रुपये ।	सरकार द्वारा मंजूर
14.	मैसर्स नाज नैरिन प्रा0 लि0 अलंग, गुजरात ।	मैसर्स अजोव शिपिंग कंपनी उकैन	शिपब्रेकिंग, शिप बिल रिडंग एण्ड शिप रिपेयल सं 4.0 बिलियन एल0डी0टी0	30 लाख रुपये	सरकार द्वारा मंजूर
15.	मैसर्स प्रतीक शिपब्रेकर्स प्रा0 लि0 सोसिया, गुजरात ।	एन0आर0आई0	शिप ब्रेकिंग इत्यादि	51 लाख रुपये	सरकार के विचाराधीन

1	2	3	4	5	6
16.	मैसर्स एशियाटिक स्टील इंडिया।	इण्डस्ट्रील इनवेस्टमेंट्स प्रा0लि0	शिपब्रेकिंग रीरोलिंग,कैलप्टिव प्रयोग के लिये आक्सीज़न गैस के उत्पादय।	584.64 लाख रुपये प्रत्यावर्तनीय आधार पर एन0आर0आई0 के 144 लाख रुपये के निवेश सहित।	सरकार के विचाराधीन
17.	मैसर्स स्वामीनारायन शिपलब्रेकिंग प्रा0 लिमिटिड	श्री मनसूख बल्लभदास भाई पटेल, एन0आर0आई0 कम्पनी के एक निदेशक	शिपब्रेकिंग,शिप-रिपेय रिंग इक्वादि।	2.55 करोड़ रुपये	सरकार के विचाराधीन
18.	मैसर्स सेसा केम्जवाल कोक कंपनी लि0, अमोना, गोल आ।	मैसर्स केम्बला कोल एण्ड कोक प्रा0 लि0 ऑस्टरेलिया	नयून राजयुक्त धातुकल मीय कोंबला 2.8 लाख वार्षिक चरण-I	40% (10 करोड़ रुपये) परियोजना लागत 65 करोड़ रुपये परिकल्पित (चरण-I)।	सरकार द्वारा मंजूर

Entitlement of MPs, MLAs and Ex-MPs for Preferential DDA Allotment

73S. SHRI K RAHMAN KHAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether MPs, MLAs and Ex-MPs are entitled for preferential or out of turn allotment of houses sites in Delhi, by DDA;

(b) whether bulk land or Houses were allotted to MPs or MLAs Cooperative Housing Society by DDA during 1992-93, 1993-94 and 1994-95, if so; the details thereof; and

(c) if not, whether Government will consider allotment of sites or houses by DDA to MPs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) It is not possible to provide any preferential treatment to MPs, Ex-MPs and MLAs keeping in view the fact that DDA has to cater to the requirements of large number of registrants who have been awaiting allotment of flats for a long time.

Marketing Strategies for Coconut

736. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for 1995-96 for better marketing strategies for coconut fanners of Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any consultation has taken place with Andhra. Pradesh Government in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARV1ND NETAM): (a) and (b) There is no specific scheme for 1995-96 for better marketing strategies for coconut farmers of Andhra Pradesh. However, Coconut Development Board extends promotional support like linking the supplier and potential buyers, make available market review and reports. The